

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 022/2020 (GCMS 2020/00047)	दायर दिनांक 25.08.2020	निर्णय दिनांक 04.03.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. रघुनाथ पिता काशीराम जाति मेवाडा आयु वयस्क, निवासी धारला तहसील, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
2. कन्हैयालाल पिता काशीराम जाति मेवाडा आयु वयस्क, निवासी धारला तहसील, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
3. उदयलाल पिता काशीराम जाति मेवाडा आयु वयस्क, निवासी धारला तहसील, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट्स**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

-:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपतहसीलदार बेगूं बमामले प्रकरण संख्या 6/2020 दिनांक 05-08-2020 ::-

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री भैरुलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.08.2020 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवार हल्का रावडदा ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्टगण अतिकमी ने मौजा धारला की बिलानाम/चारागाह आराजी नम्बर 533 मी रकबा 3.10 हेक्टर में से 1.10 हेक्टर भूमि पर संवत् 2076 में अतिक्रमण कर मौके पर पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण कर लिया है व अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि गत वर्ष भी इन्ही अतिक्रमियों ने इसी भूमि पर अतिक्रमण किया था जिन्हे मिसल संख्या 2/2020 निर्णय दिनांक 19.03.2020 से बेदखल किया गया



था, जिससे यह पश्चातवृत्ति अतिक्रमण है, जिन्हे उक्त आराजीयात से बेदखल किया जावे। उक्त रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.07.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्दगण अतिक्रमियों के सम्मन नोटिस जारी किये व आगामी तारीख पेशी 31.07.2020 नियत की गयी व 31.07.2020 को अपीलान्दगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा जिसमे आगामी पेशी दिनांक 05.08.2020 नियत की गयी। दिनांक 05.08.2020 को अपीलान्दगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। अपीलान्दगण का कब्जा पुराना है। पुराने कब्जे के दस्तावेज प्रस्तुत करने में समय लगने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में अपीलान्दगण की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तलब करायी जावे। उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बगैर विचारण न्यायालय ने बिना जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य के निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 05.03.2020 मे जवाब सारहीन होने का उल्लेख करते हुए जो निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलान्द ने दिनांक 31.07.2020 को जवाब हेतु अवसर चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया व दिनांक 05.08.2020 की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 05.08.2020 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया गया। जिसका निस्तारण किये बगैर विचारण न्यायालय ने जवाब सारहीन होना पाया जाकर बेदखल किय जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्दगण ने दिनांक 05.08.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी बिलानाम सरकार काबिल काशत भूमि है। मौके पर अपीलान्दगण ने फसल खरीब की काशत कर रखी है, ऐसी स्थिति में अपीलान्दगण को बेदखल किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है, फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये विवादित आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पर्चा मौका पर पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये बगैर पर्चा मौका साबित हो जाना मानते हुए निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश, विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के होने से अपील अपीलान्दगण न्यायालय आप में पेश है। अपील अपीलान्दगण अन्दर मयाद 30 दिन पेश है। अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जावेगें। अंत में अपीलान्दस द्वारा प्रार्थना की गई कि अपील बहक



अपीलान्टगण विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 निरस्त फरमाया जाकर मौजा धारला की आराजी नम्बर 533 मी रकबा 1.10 हेक्टर भूमि अपीलान्टगण का पुराना कब्जा होने से नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाये।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बेंगू के पत्रांक/राजस्व/2020/1200 दिनांक 16.09.2020 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 006/2020 अनवानी सरकार बनाम रघुनाथ पिता काशीराम मेवाडा निवासी धारला वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 04.03.2021 को उभयपक्ष हाजिर आये। अपील अपीलांट्स अन्दर मियाद अवधि पेश की गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब अपील में पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पटवार हल्का रावडदा ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्टगण अतिक्रमी ने मौजा धारला की बिलानाम/चारागाह आराजी नम्बर 533 मी रकबा 3.10 हेक्टर में से 1.10 हेक्टर भूमि पर संवत् 2076 में अतिक्रमण कर मौके पर पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण कर लिया है व अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि गत वर्ष भी इन्ही अतिक्रमियों ने इसी भूमि पर अतिक्रमण किया था जिन्हे मिसल संख्या 2/2020 निर्णय दिनांक 19.03.2020 से बेदखल किया गया था, जिससे यह पश्चातवृत्ति अतिक्रमण है, जिन्हे उक्त आराजीयात से बेदखल किया जावे। इस पर अपीलान्टगण अतिक्रमियों के सम्मन नोटिस जारी किये व आगामी तारीख पेशी 31.07.2020 नियत की गयी व 31.07.2020 को अपीलान्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा जिसमे आगामी पेशी दिनांक 05.08.2020 नियत की गयी। दिनांक 05.08.2020 को अपीलान्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रार्थनापत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 05.08.2020 मे जवाब सारहीन होने का उल्लेख करते हुए जो निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलान्ट ने दिनांक 31.07.2020 को जवाब हेतु अवसर चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया व दिनांक 05.08.2020 की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 05.08.2020 को जवाब प्रस्तुत नहीं किया



जाकर मौका रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया गया। जिसका निस्तारण किये बगैर विचारण न्यायालय ने जवाब सारहीन होना पाया जाकर बेदखल किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, बेंगू के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्दगण ने फसल खरीब की काश्त कर रखी है, ऐसी स्थिति में अपीलान्दगण को बेदखल किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है, फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये विवादित आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पर्चा मौका पर पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये बगैर पर्चा मौका साबित हो जाना मानते हुए निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty



which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent act of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic prison for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :



Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बेंगू ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांत स्वयं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही पत्रावली पर अपीलांत द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलांट्स का विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार को कोई हक-हकूक निहित है। अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2020 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार, बेंगू के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगू द्वारा अपने प्रकरण संख्या 006/2020 अनवानी सरकार बनाम रघुनाथ वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 को यथावत रखा जाता है, एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स को भौतिक रूप से विवादित आराजीयात से बेदखल किया जाकर पालना से अवगत कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 04.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़